हार का कोई सबसे बड़ा कारण है तो वो है डर।

– अज्ञात

लॉकडाउन से होने वाला नुकसान

केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से कई छूटें घोषित की हैं, साथ ही आगे की छूटों के बारे में फैसला राज्य सरकारों और जिला प्रशासन पर छोड़ा है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार राज्यों को और कंटेनमेंट जोन तथा बफर जोन तय करने का जिम्मा जिला प्रशासन को सौंप दिया गया है।

अमित अग्रवाल।

तमाम आशंकाओं और आपत्तियों के बीच भारत में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है, जो 31 मई तक चलना है। इससे पहले कई तरफ से यह बात उठी थी कि लॉकडाउन ने कोरोना वायरस के फैलाव को बेकाबू होने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन अब देश इस स्थिति में पहुंच रहा है कि लॉकडाउन से होने वाला नुकसान इसके फायदे को बहुत पीछे छोड़ सकता है। आर्थिक गतिविधियों का ठप पड़े रहना न सिर्फ करोड़ों लोगों को बेरोजगार बना सकता है, बल्कि समूची व्यवस्था के सामने गंभीर खतरे खड़े कर सकता है।

संभवतः इसीलिए लॉकडाउन का चौथा चरण घोषित करते हुए केंद्र सरकार ने साफ कहा कि सारे सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के साथ ही इस चरण में ज्यादा जोर आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने और जनजीवन को सामान्य बनाने पर रहेगा। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से कई छूटें घोषित की हैं, साथ ही आगे की छूटों के बारे में फैसला राज्य सरकारों और जिला प्रशासन पर छोड़ा है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार राज्यों को और कंटेनमेंट जोन तथा बफर जोन तय करने का जिम्मा जिला प्रशासन को सौंप दिया गया है।

राज्य सरकारें जमीनी स्थितियों से बेहतर ढंग से वाकिफ होती हैं, इसलिए प्रदेश के अलग–अलग हिस्सों में बीमारी के फैलाव के खतरों और आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त फैसला वे ज्यादा आसानी से कर सकती हैं। इसका असर भी पहले दिन से ही दिखने लगा। दिल्ली में एम्स अस्पताल ने इसी सप्ताह ओपीडी खोलने का फैसला करते हुए इसकी तैयारी शुरू कर दी है, जबकि पंजाब सरकार ने अन्य राज्यों से कैब और निजी वाहनों के आने की मंजूरी दे दी है।

कर्नाटक सरकार ने राज्य के अंदर बस, ऑटो और निजी वाहनों के चलने की इजाजत दे दी है, साथ ही उन्हें पैसेंजरों की संख्या कम रखने और अन्य सावधानियां बरतने के सख्त निर्देश भी दिए हैं। राज्यों पर फैसला छोड़ने का एक मतलब यह भी है कि इस चरण में सबके बीच सामंजस्य बनाना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इसका संकेत पहले ही दिन कर्नाटक सरकार के उस फैसले से मिला जिसमें उसने साफ कहा कि चार राज्यों– महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और केरल से लोगों के उसकी सीमा में आने पर 31 मई तक रोक लगी रहेगी।

उम्मीद की जानी चाहिए कि ये चारों राज्य इसे अपने खिलाफ उठाया गया कदम मानकर प्रतिशोधात्मक कार्रवाई का रास्ता नहीं अपनाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो कोरोना से निपटने और आर्थिक मंदी से बचने की दुतरफा चुनौती से जूझने का हमारा संकल्प अधूरा ही रह जाएगा। बेहतर होगा कि लोकल लेवल पर बीमारी से सर्वश्रेष्ठ तरीके से लड़ाई जारी रखते हुए भी हम अपने नजरिये को राष्ट्रीय बनाए रखें।

यह केंद्र सरकार के राजनीतिक कौशल का इम्तहान भी है क्योंकि राज्यों में तालमेल बनाए रखने की जिम्मेदारी अंततः उसी की है।

एक समस्या

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा। राजा ने अपने वजीर को बुलाया और उसे भीख की कटोरी को हीरा, माणिक और पन्ने जैसी कीमती पत्थरों से भर देने को कहा. इस भिखारी को भी पता चले कि यह किससे बात कर रहा है! लेकिन तभी एक समस्या आ गई. कटोरी भर गया था लेकिन राजा आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि जैसे ही रत्न कटोरी में गिरते, वह गायब हो जाते. कटोरी को कई बार भरा गया लेकिन हर बार वह फिर से खाली हो जाता था. अब राजा गुस्से में आ गया लेकिन उसने अपने वजीर से कहा, "भले ही मेरा पूरा राज्य चला जाए या मेरा पूरा खजाना खाली हो जाए लेकिन मैं इस भिखारी को मुझे हराने नहीं दूंगा. अब यह कुछ ज्यादा ही हो गया है." जैसा राजा ने कहा वैसा ही हुआ. यह कहा जाता है कि उसका पूरा खजाना गायब हो गया।

संपादकीय

वायरस का कहर जारी

देश–दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है। लॉकडाउन को भी करीब–करीब दो महीने हो रहे हैं। भूख और हालात से लाचार प्रवासी मजदूरों के सब्र का बांध टूट चुका है। वे अब बिना किसी से कोई उम्मीद रखे सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर पैदल ही निकल पड़े हैं। इस दौरान रोज हमारे सामने मजदूरों के दिल दहला देने वाले किस्से भी सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये प्रवासी मजदूर अपने घरों को जाने के बजाय किसी नेता की चुनावी रैली में शामिल होने जा रहे होते तो भी इनकी हालत इतनी ही बदतर होती? बिल्कुल भी नहीं।

अपने देश में चुनाव त्योहारों की तरह होते हैं। पूरे साल कहीं न कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। वैसे भी चुनाव को तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व कहा ही जाता है। ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, कुछ समय पहले महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए। उससे पहले देश में लोकसभा के भी चुनाव हुए थे। इन चुनावों के दौरान आपने बड़ी–बड़ी रैलियां देखी होंगी और इन रैलियों में लाखों की संख्या में आए लोग भी। कौन थे ये लोग और कहां से आए थे? जाहिर सी बात है विदेश से तो नहीं आए होंगे, हमारे और आपके बीच के रहे होंगे।

खैर समय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह बीतता जरूर है और हर किसी का हिसाब भी रखता है। प्रवासी मजदूरों की मौजूदा हालत देखकर इस कथन पर विश्वास और दृढ़ हो जाता है कि गरीबी एक अभिशाप है, वरना चुनावी रैलियों में पलकों पर बिठाकर पहुंचाए जाने वाले इन मजदूरों को आज सड़कों पर इस तरह भटकना नहीं पड़ता।

देखिए! आजकल सरकारें जनता से कम विपक्ष से अधिक परेशान हैं। क्योंकि जनता तो बेचारी है और कोरोना की मारी है। लेकिन विपक्ष की साजिश से लड़ने के लिए सरकार की इम्युनिटी दुरुस्त होनी चाहिए।

सरकार हो या बस

प्रभुनाथ शुक्ल

फिट रहना बेहद जरूरी है। वह सरकार हो या बस। अपन के मुलुक में फिट रहने का आजकल हर कोई मंत्र बाँटता है। यह विधा स्किल डेवलपमेंट में आती है। सरकार भी फिट और हिट रहने के लिए बाकायदा योगमंत्र बांटती रहती हैं। अपने राजनेता ट्वीटर पर वीडियो भी अपलोड करते रहते हैं। कोरोना काल में फिट और हिट का मंत्र सब की जुबान पर है। राजनेता, अभिनेता, खिलाड़ी और डॉक्टर, आयुर्वेदाचार्य सब अपनी तरफ से ज्ञान बाँटते दिख जाएंगे। घर में रखे बुद्धू बक्से पर तो दिन भर यह मंत्र मुफ्त में बाँटा जाता है। कहा जाता है की तंदुरूस्ती लाख नियामत है। अपने बाबा तो ट्वेंटी फोर ऑवर एक्टिव मोड पर रहते हैं। टीवी की एंकराईन की हल्की मुस्कराहट की भनक पाते ही बाबा जी अनुलोम– विलोम से शुरू हो कर यू से जेड तक बन जाते हैं। क्योंकि कोरोना काल में इम्युनिटी बढ़ाने सवाल है। आजकल इंसानों के साथ बसों का भी फिटनेस माँगा जाने लगा है। क्योंकि इस दौर में फिटनेस और इम्युनिटी की सख्त जरूरत है। सरकारें कभी फिटनेस से समझौता नहीं करती हैं। वह एक्स्ट्रा इनर्जी रखती हैं क्योंकि उन्हें विपक्ष के तीखे वार को झेलना पड़ता है। वह जानती हैं कि सियासत के इस दौर में फिटनेस जरूरी है , वरना चालाक विपक्ष से उबरना मुश्किल है। क्योंकि आजकल विपक्ष जादुई करामात से भरा है। वह तिल को ताड़ और ताड़ को तिल बनाना अच्छी तरह जानता है। वह बसों को टेम्पो, टेम्पो को बाइक और बाइक को स्कूटी बनाने में माहिर है। इस तरह की अचानक आयीं सियासी आपदाएं सरकार को मुश्किल में डालती हैं। फिर सरकार को दोष देना उचित नहीं है।

देखिए! आजकल सरकारें जनता से कम विपक्ष से अधिक परेशान हैं। क्योंकि जनता तो बेचारी है और कोरोना की मारी है। लेकिन विपक्ष की साजिश से लड़ने के लिए सरकार की इम्युनिटी दुरुस्त होनी चाहिए। विपक्ष सरकारों को बदनाम करने की जुगत खोजती रहती है। वह बस को टेम्पो इसी तरह बनाती रहती है। अब सरकार सतर्क न रहती तो जाने क्या हो जाता। सरकार की इसी सतर्कता से विपक्ष की साजिश बेनकाब हो गई। अरे भाई सवाल मजदूरों की सुरक्षा का है। मजदूरों की सुरक्षा सरकारों का दायित्व है। जिंदा न सही तो मुर्दा ही सही उन्हें घरों तक पहुँचाना राष्ट्रीय कर्तव्य है। क्योंकि चुनावों के दौरान किए गए वादों का यह पवित्र मौसम है।

आप क्या चाहते हैं कि सरकार राजनीति के बजाय सिर्फ मजदूरों को भेजने पर अपना ध्यान देती। लेकिन कोई हादसा हो जाता तो विपक्ष सरकार पर तीखा हमला बोल देता। राजनीति का नया दौर शुरू हो जाता। सरकार जब तक हादसे और मामले की जांच का आदेश देती उसके पहले विपक्ष बसों की दूसरी सूची पेश कर देता कि हमने तो सारी की सारी बसें उपलब्ध कराई थी। यह हादसा कैसे हुआ। निश्चित रुप से यह सरकार की साजिश हो सकतीं है। फिर सरकार तो सरकार होती है। विपक्ष की यहीं जिम्मेदारी तो सरकार पूर्व में निभा कर आती है। क्योंकि आज की सरकार भी कल की विपक्ष होती है। शायद विपक्ष यह बात समझने में नाकाम रहा है।

इसिलए सरकार बार–बार बसों के फिटनेस की माँग करती हैं। सरकारों को विपक्ष की गहरी साजिश हमेशा सतर्क मोड पर रखती है।

सूडोकु नवताल-5336

सरल

3	9			1	4			2
1	2		6		3		5	
		5		8	7			9
	7			6	9			8
2	1			5			4	6
4			3	2			9	
9			8	4		5		
	6		9		5		2	4
8			1	7			6	3

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5335 का हल

6	9	2	3	7	4	5	8	1
3	8	5	6	2	1	7	4	9
7	4	1	8	9	5	6	2	3
2	3	9	5	4	6	8	1	7
1	7	4	9	8	3	2	6	5
5	6	8	7	1	2	9	3	4
4	5	7	1	6	8	3	9	2
8	2	3	4	5	9	1	7	6
9	1	6	2	3	7	4	5	8

अपना ब्लॉग

मजदूर सड़क नापने को मबदूर

मोहन। गरीब और मजदूरों के नाम की पवित्र माला जप सरकारें बनती बिगड़ती रहीं हैं। फिर बसें दूसरे राज्य से आई थी। वहां विपक्ष की सरकार हैं। सरकारी सूत्रों का कहना था कि बसें कोरोना संक्रमित हो सकतीं थी। बेचारे मजदूर भी इस साजिश का शिकार हो सकते थे। सरकार की फजीहत सो अलग से होती। लिहाजा सरकार ने फिटनेस की जांच करा कम से कम खुद को तो सुरक्षित कर लिया। उधर बेचारे मजबूर मजदूर सड़क नापने को मजदूर थे। उनका कहना था कि अभी चलते रहो क्योंकि राजनीति चल रहीं है। जब बस चलेगी तो देखा जाएगा। राजनीति के लिए यह आपदा में अवसर तलाशने का वक्त है। अभी चुनाव दूर हैं इसलिए हम मजदूर कम मजबूर अधिक हैं। समझे साधो! फिर सियासत का डंडा एक दूसरे पर चलने लगा। अरे भाई! चले भी क्यों ना। सवाल गरीब मजदूरों की सुरक्षा और अधिकार का है।